types of family oriented projects to be implemented in a most effective manner; and

14. A new system of concurrent evaluation on the basis of taking up 36 districts, 72 blocks and a group of 10 current beneficiaries and 10 beneficiaries who received their assistance two years ago, per month has been introduced to have a closer monitoring of the programme.

FAO recommendations for price incentives

*247. SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the FAO experts have recently suggested that India must give appropriate price incentives to its farmers to raise agricultural production;

(b) whether they have also stated that if adequate price and market is assured to the farmers, abundant production of crops is possible;

(c) if so, what are the other suggestions made by the FAO experts and whether Government have examined those suggestions; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI G. S. DHILLON): (a) and (b) No, Sir. No such suggestions have been made to the Government of India by any FAO experts.

(c) and (d) Do not arise.

दिल्ली दुग्ध योजना के डिपुओं में विद्यार्थियों को हटा कर भूतपूर्व सैनिकों का लगाया जाना

*248. **श्री सूरज प्रसाद :**
श्री जे० पी० गोयल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना (डी० एम० एस०) का दुग्ध-वितरण संबंधी कार्य अनेक वर्षों से विद्यार्थियों द्वारा किया जा रहा है तथा प्रत्येक डिपो पर वरिष्ठ और कनिष्ठ डिपो अभिकर्ताओं के रूप में तैनात विद्यार्थियों को प्रति माह क्रमश: 180 रुपये और 120 रुपए का भुगतान किया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इन विद्यार्थियों के स्थान पर भूतपूर्व सैनिकों को कमीशन के आधार पर लगाने का निर्णय किया है, जिसके फलस्वरूप निर्धन परिवारों के इन विद्यार्थियों को अपने शिक्षा-संबंधी खर्चे पूरे करने में अत्यधिक कठिनाई होने की संभावना है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन भूतपूर्व सैनिकों को, उन्हें इन दूध के डिपुओं का आवंटन करने के बजाय किन्हीं स्थायी पदों पर नियुक्त करने का विचार रखती है, क्योंकि इन डिपुओं से उन्हें प्रतिमाह 180 रुपए या 240 रुपए की आय ही होगी जो कि उनके लिए अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी; और

(घ) क्या इन डिपुओं पर कार्यरत विद्यार्थियों ने इस संबंध में सरकार को कोई विरोध-पत्र प्रस्तुत किया है, और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

कृषि मंत्री (श्री जी० एस० ढिल्लों) : (क) जी, हां। वरिष्ठ डिपो एजेंटों के रूप में तैनात विद्यार्थियों को 6 रुपए प्रति दिन प्रति ड्यूटी और डिपो एजेंटों को 4 रुपए प्रति दिन प्रति ड्यूटी के हिसाब से अदायगी की जाती है।

(ख) यह फैसला किया गया है कि चरणबद्ध पद्धति से डिपो एजेंटों के स्थान पर धीरे-धीरे भूतपूर्व सैनिकों को रखा जाए, क्योंकि ऐसी व्यवस्था से दूध का अधिक लम्बी अवधि तक बिक्री के लिए उपलब्ध होना सुनिश्चित हो जाएगा। बिक्री से अर्जित धन को क्रास्ड चैकों द्वारा एकत्र करना सरल हो जाएगा